भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1523

12.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण को बढ़ावा देना

1523 **श्री लहर सिंह सिरोयाः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम (फेम) योजना के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में स्वीकृत और संस्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या क्या है; और

(ग) इन पहलों का ऑटोमोबाइल क्षेत्र और रोजगार सृजन पर समग्रत: क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): फ़ेम-II स्कीम के तहत, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय मूल्य में सीधे कटौती के रूप में कंज्यूमर्स (खरीदारों/अंतिम प्रयोक्ता) को मांग प्रोत्साहन दिए गए, जिससे इन वाहनों के व्यापक अंगीकरण में मदद मिली। इन प्रोत्साहनों की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम, यानी ईवी विनिर्माताओं) को की गई। फ़ेम-II स्कीम के तहत मूल उपकरण विनिर्माताओं को 6,559 करोड़ रुपये के मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूति की गई, जो 31/03/2024 को खत्म हो गई।

(ख): तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार, फेम-II स्कीम के तहत कर्नाटक में स्वीकृत और संस्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 751 है।

(ग): फ़ेम-II स्कीम के कारण बाजार में ईवी की पहुंच में काफी बढ़ोतरी हुई, ईवी अंगीकरण का स्तर वित्त वर्ष 2019-20 में 0.71% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 7.50% हो गया। इस स्कीम ने 16,71,606 इलेक्ट्रिक वाहनों (31 मार्च, 2025 तक) की बिक्री में मदद की और तैनाती के लिए 6,862 ई-बसों को मंजूरी दी। फ़ेम-II ने अनिवार्य चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के ज़रिए घरेलू विनिर्माण को भी मज़बूत किया, जिसके लिए ईवी के मुख्य घटकों का धीरे-धीरे स्थानीयकरण ज़रूरी था। इससे घरेलू ईवी इकोसिस्टम का विस्तार हुआ, विनिर्माण में निवेश बढ़ा, और एक मज़बूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का विकास हुआ। कुल मिलाकर, इन पहलों से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन करने में भी मदद मिली।

****